उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 14 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(07/64)**

राज्य में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 15745 हैं। इनमें से 15681 ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है। 99.59 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने में उत्तराखण्ड देश में अग्रणी है। मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी ने शुक्रवार को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बताया कि 29 ग्रामों की विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। यह कार्य दिसम्बर 2017 तक पूरे हो जायेंगे।

प्रभारी सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि शेष 64 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 48 ग्राम ग्रिड और 16 ग्राम ऑफ ग्रिड से जुडेंगे। दिसम्बर, 2017 तक 29 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमे से 13 ग्राम ग्रिड और 16 ग्राम ऑफ ग्रिड के होंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जनपदों के जिलाधिकारियों और डीएफओ को निर्देश दिये गये कि फारेस्ट क्लियरेंस के कार्य में तेजी लायें। राजस्व, वन और विद्युत विभागों में समन्वय के लिये नोडल अधिकारी तैनात किये जाये। निदेशक यूपीसीएल और निदेशक परियोजना इन जनपदों का मौका मुआयना कर कार्य में तेजी लाए।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014

देहरादून 14 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/63)**

आज दिनांक 14.07.2017 को उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12.07.2017 को अतिवृष्टि से जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर, ऋषिकेश एवं डोईवाला में कुल–46 भवन क्षतिग्रस्त हुये हैं। साथ ही दिनांक 13.07.2017 को जनपद चमोली के तहसील थराली के क्वारी बुग्याल के ग्राम–बलाण में अतिवृष्टि से कुल पशु हानि–25 (3 बड़े पशु एवं 22 बकरियां) तथा 03 भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त के अतिरिक्त जनपद चम्पावत में भी 02 पशु हानि तथा 01 भवन, बागेश्वर 04, टिहरी 02, पिथौरागढ 04 क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।

दिनांक 14.07.2017 को उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में कुल 338 अवरूद्ध मार्गों में से 138 मार्गों को आज दिनांक 14.07.2017 को यातायात हेतु खोल दिया गया है तथा शेष 200 मुख्य राज्य मार्गों/ग्रामीण मार्गों को खोलने का कार्य प्रगति पर है। चारधाम यात्रा के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हेतु खुले हुये हैं। प्रदेश के सभी नदियाँ खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं।

वर्तमान में उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में SDRF की 48 टीमें, NDRF की 4 टीमें ;देहरादून, अल्मोड़ा, गौचर व मिर्थी पिथौरागढ़) एवं आपदा प्रबन्धन की 16 टीमें खोज एवं बचाव कार्य हेतु तैनात हैं। मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून से आज दोपहर प्राप्त मौसम सम्बन्धी चेतावनी के अनुसार दिनांक 16.07.2017 को जनपद चमोली तथा 17.07.2017 को चमोली, देहरादून व उत्तरकाशी जनपदों के कुछ स्थानों में भारी वर्षा (64.5–115.5 मिलीमीटर) होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। मौसम सम्बन्धी प्राप्त चेतावनी को, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों एवं पुलिस प्रमुखों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तत्पर रखे जाने के साथ ही किसी भी आपदा की स्थिति में प्रतिवादन का उच्च स्तर बनाये जाने हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

नोट– **राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।**

देहरादून 14 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(07/63)**

लखवाड़ परियोजना के लिए केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा शीघ्र ही बजटीय प्रावधान कर दिया जाएगा। यह जानकारी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार ने दी है। उन्होने बताया कि इस मामले में कैबिनेट सचिव श्री पी0के0सिन्हा से उनकी नई दिल्ली में मुलाकात हुई है और कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया है कि 300 मेगावाट की इस परियोजना के लिए भारत सरकार के स्तर से शीघ्र धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना में दिसम्बर, 2018 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगी। और लखवाड़ परियोजना अगले चार साल में बनकर तैयार हो जायेगी। उन्होने बताया कि लखवाड़ परियोजना के लिये भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही Investment Clearence दी जा चुकी है। श्री कुमार ने बताया कि उन्होने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष गिरीश प्रधान से भी नई दिल्ली में मुलाकात की और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पिटकुल के लम्बित प्रकरण पर चर्चा की। उन्होने बताया कि उक्त केन्द्रीय आयोग ने श्रीनगर–अलकनन्दा पावर प्रोजेक्ट का पावर गेट पीटकुल को दिया गया था और इसमें पिटकुल को 50 करोड़ रूपये दिया जाना था जिस पर अभी निर्णय

नही हुआ है। इस टैरीफ को पीटकुल को देने के लिए उन्होने श्री प्रधान से अनुरोध किया। श्री प्रधान ने इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(07/61)**

मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पंचेश्वर बांध परियोजना के बारे में सम्बंधित जिलाधिकारियों से समयबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। बताया कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना लगातार मानिटरिंग भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होने वन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग और पंचेश्वर डैम एथार्टी डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने की तिथि जल्द तय करने के निर्देश दिए। प्रभावित जनपद चंपावत के जिलाधिकारी ने बताया कि जन सुनवाई की तिथि 9 अगस्त को तय की गई है। पिथौरागढ़ की जन सुनवाई 11 अगस्त और अल्मोड़ा की 17 अगस्त 2017 तय की गई है। मुख्य सचिव ने इसके लिए कम से कम वन भूमि का प्रमाणपत्र, बांज वृक्ष प्रभावित न होने, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और परियोजना विशेष स्थल पर होने का प्रमाणपत्र जल्द से तैयार कर लें। मुख्य सचिव ने सभी कार्यों के लिए टाइम फ्रेम तय करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि 5040 मेगावाट क्षमता की पंचेश्वर बांध परियोजना का निर्माण काली नदी पर नेपाल और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रुप से किया जाना है। परियोजना के भूमि अधिग्रहण, डूब क्षेत्र सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना आदि के लिए उपमहाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को नामित किया गया है। पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण महाकाली और सरजू नदियों के संगम स्थल से नदी के बहाव में 25 किमी नीचे पंचेश्वर बांध परियोजना (48000 मेगावाट) का निर्माण होना है। इस परियोजना से 27 किमी नीचे की ओर रुपालीगाड बांध परियोजना (240 मेगावाट) का निर्माण होना है। पंचेश्वर बांध का निर्माण 29,483 करोड़ रुपए और रूपालीगाड बांध का निर्माण 3,625 करोड़ रुपए से प्रस्तावित है। इससे उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जनपद प्रभावित होंगे। इन जनपदों के 122 गांव के 29436 परिवार प्रभावित होंगे। रुपालीगाड़ बांध परियोजना से चंपावत जिले के 11 गांव के 1587 परिवार प्रभावित होंगे। परियोजना से 7678 मि.यू. और रुपालीगाड बांध से 1438 मि.यू. बिजली उत्पादन का अनुमान है। इससे भारत को 259000 हेक्टेयर और नेपाल को 170000 हेक्टेयर सिंचाई का अतिरिक्त लाभ होगा। शारदा नदी में आने वाली बाढ़ पर भी नियंत्रण होगा, जिससे 90 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उत्तराखंड को इन परियोजनाओं से 12 प्रतिशत (302 मेगावाट) निःशुल्क रायल्टी उर्जा के रूप में और स्थानीय विकास कोष के लिए 1 प्रतिशत (25 मेगावाट) निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त होगी।

बैठक में प्रभारी सचिव ऊर्जा राधिक झा, अपर सचिव उर्जा रणवीर सिंह चौहान, नोडल अधिकारी विनीत पांगती, एमडी यूजेवीएनएल एसएनवर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014